# अगस्त क्रान्ति की समाजवादी दिशा

समाजवादी पार्टी

## बाइस में बाइसिकल

www.samajwadiparty.in

# सम्मानित भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों,

9 अगस्त 1942 का दिन 1857 की क्रान्ति के बाद ब्रिटिशराज से भारत के मुक्ति संघर्ष का ऐतिहासिक दिन है। स्वतंत्रता आंदोलन की यह अंतिम और निर्णायक लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश सत्ता की जड़े हिला दी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो आंदोलन' अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने का अंतिम अल्टीमेटम भी था।

8 अगस्त 1942 को रात में 'अंग्रेजों भारत छोड़ों' प्रस्ताव पास हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर ऐतिहासिक आव्हान किया– ''करो या मरोः या तो स्वाधीनता प्राप्त कर लो या मर मिटो।'' उन्होंने कहा– ''मैं अंग्रेजो को चेतावनी देता हूँ या तो खुद ही भारत का शासन भारतीयों के हाथों में सौंपकर यहां से चले जाओं, अन्यथा तुम्हें सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र की उमड़ती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा।''

महात्मा गांधी ने समाचार पत्रों, नरेशों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य सभी का आवाहन करते हुए कहाः ''अबकी जो लड़ाई छिड़ेगी, वह तो सामूहिक लड़ाई होगी।''

बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें कहा गया कि ''भारत अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। अंग्रेज भारत छोड़ दें। देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरूद्ध अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अब उसे उस बिन्दु से लौटाने का औचित्य नहीं है। अतः अहिसंक ढंग से, व्यापक धरातल पर गांधीजी के नेतृत्व में जनसंघर्ष शुरू करने का निर्णय लेते है।''

महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव पर 70 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने कहा–'मैं आपको एक मंत्र देता हूं करो या मरो।' प्रस्ताव पास होने के बाद ही आधीरात से ब्रिटिश सरकार ने नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद आदि गिरफ्तार कर लिए गए।

तय कार्यक्रम के अनुसार 9 अगस्त 1942 को क्रान्ति दिवस का एलान किया गया था। बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान के चारों तरफ उस दिन पुलिस तैनात थी। किन्तु आश्चर्य, अरूणा आसफ अली ने मैदान में तिरंगा फहरा ही दिया। इसके बाद तो पूरे देश में हलचल मच गई। समाजवादी साथियों ने तब नेतृत्व सम्हाल लिया।

अगस्त क्रान्ति आंदोलन को व्यापक बनाने में श्री जयप्रकाश नारायण, डॉ0 राममनोहर लोहिया, अग्रणी रहे। अच्युत पटवर्धन, रामनंदन मिश्र, एस.एम. जोशी, यूसुफ मेहर अली भी उनके साथ थे। अरूणा आसफ अली के साथ सुचेता कृपलानी, ऊषा मेहता, माया, वनलता सेन ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। हजारीबाग जेल में बंदी जयप्रकाश नारायण जेल की दीवार फांदकर बाहर आ गए। उन्हें जनता ने एक हीरो जैसा सम्मान दिया। डॉ0 राममनोहर लोहिया ने उषा मेहता, बिट्ठल दास रखवाकर (बाबू भाई), चन्द्रकांत झावेरी और बिट्ठल झावेरी जैसे नौजवानों को साथ लेकर रेडियो स्थापित कर 2 सितम्बर 1942 से प्रसारण सेवा शुरू की। यह प्रसारण 11 नवम्बर 1942 तक चला। डॉ0 राममनोहर लोहिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं।

लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए गांधी जी ने जहाज पर नवम्बर 1909 में 'हिन्द स्वराज' पुस्तक लिखी थी जिसे 1910 में अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। गांधी जी ने ग्राम विकास को केन्द्र में लाकर वैकल्पिक टेक्नोलॉजी, स्वदेशी का प्रसार तथा सर्वोदय को महत्व देते हुए लोक का पक्ष लिया था। गांधी जी कहते थे मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। हमारा स्वराज तभी पूर्ण

स्वराज होगा, जब जीवन की आवश्यक सुविधाएं हमें उपलब्ध हों। आर्थिक समानता अहिंसापूर्ण स्वराज की चाभी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने का अर्थ है पूंजी और मजदूरी के बीच झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना।

विचारधारा किसी भी राजनीतिक दल की नींव होती है। समाजवादी विचारधारा व्यक्ति के साथ सामाजिक समानता पर बल देती है। समाज उसी विचारधारा को स्वीकार करता है जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। समाजवादी पार्टी बदलते समय के अनुसार अपनी विचारधारा को वर्तमान समाज की चुनौतियों और सरोकारों से जोड़कर देखती है।

समाजवादी आन्दोलन के प्रेरणा पुरूष डॉ0 राममनोहर लोहिया की मान्यता थी कि एक गरीब देश में राजनीति का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों का पेट भरना, अगर लोगों का पेट नहीं भरता तो फिर उस देश की राजनीति निकम्मी और असफल है। आज नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इन्हें दूर करके ही खुशहाल समाज की तरक्की का निर्माण किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में इन विचारों को धरती पर उतारने और खेती–गांव की तरक्की के लिए 2012–2017 की समाजवादी सरकार ने बजट में विशेष व्यवस्थाएं की थी। शहरों और गांवों के बीच संतुलन बनाने का भी काम हुआ था। गांवों में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की गई और किसान को आर्थिक सुरक्षा दी गई। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के किनारे मंडियों की व्यवस्था इसीलिए की गई जिससे किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके। इसी तरह समाजवादी सरकार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे बनना शुरू हुआ था, जिसे भाजपा सरकार साढ़े तीन वर्ष में भी पूरा नहीं कर सकी।

समाजवादी पार्टी की मान्यता है कि पूंजीवाद के विरूद्ध समाजवादी व्यवस्था को अपनाकर ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि में हो रहे घाटे को पूरा करना और निश्चित मुनाफा देना सरकार का दायित्व है। किसान का अपना बाजार होना चाहिए। अन्यथा किसानों की आत्महत्या नहीं रूकेगी। मंडियों के विस्तार से किसान अपनी फसल के लाभप्रद मूल्य पा सकेगा और बिचौलियों की लूट से बचेगा। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए। इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश से बचना देशहित में होगा। कृषि में विदेशी निवेश वस्तुतः किसानों का उनके खेतों से स्वामित्व छीनना होगा। किसान गुलाम बनकर निवेशक की इच्छानुसार फसल बोने और बेचने को बाध्य होगा।

सन् 1942 की अगस्त क्रान्ति की अवधारणा 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' के आधार पर सन् 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वैचारिक आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करने का लक्ष्य है। इसके लिए समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्षरत हैं। प्रगति को प्राथमिकता देने के साथ सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना है। जेपी–लोहिया के रास्ते पर समाजवादी पार्टी चलने को संकल्पित है।

25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा और सत्ता के दुरूपयोग का दौर शुरू हुआ लेकिन लोकतंत्र विरोधी निर्णयों के खिलाफ जनता में जो आक्रोश पैदा हुआ वह इतिहास का एक जीवंत पृष्ठ है। खेद है कि भाजपा ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। सत्ता में आने पर भाजपा ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 'सम्पूर्ण क्रान्ति' से उपजे मुद्दों की भी अनदेखी कर दी। जेपी आंदोलन के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मंहगाई, गरीबी के अलावा लोकतंत्र मुख्य मुद्दे थे। भाजपा ने विनाशकारी रास्ता अपना लिया है और लोकतंत्र की आवाज को अनसुना कर दिया। सत्ता पर एकाधिकारी मानसिकता भाजपा में कूट कूटकर भरी हुई है। गरीबों पर अन्याय और भ्रष्टाचार भाजपाराज में थम नहीं रहा है

और जनता को परेशान करने वाली गलत आर्थिक नीतियों के चलते लोग त्रस्त हैं।

सन् 1942 के आंदोलन में बड़े पैमाने पर शहरी जनता, किसानों और ग्रामीणों में अद्भुत चेतना जगी थी, जिसके फलस्वरूप राजनैतिक सत्ता में वे साझेदारी मांगने लगे। परन्तु आज भी सही मायनों में राजनीतिक प्रशासन और आर्थिक व्यवहार में पिछड़े और दलित वर्ग को समुचित साझेदारी नहीं मिल पाई है। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबको सम्मानजनक जीने का अधिकार मिले इसके लिए समाजवादी मानते हैं कि सामाजिक न्याय और सौहार्द के साथ ही व्यक्ति और समाज की जब आर्थिक प्रगति होगी तभी लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध होगी। डॉ0 लोहिया की 'सप्तक्रान्ति' की कल्पना नए समाज की रचना का आधार है।

वैसे भी आज विचारधाराओं में टकराव है। एक तरफ लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ अपने को सर्वोपरि दिखाने की एकाधिकारवादी मानसिकता। हमें तय करना है कि किधर जाना है? मूल अधिकार उस समाज और व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं जो कानून के प्रति आदर रखते हैं, जो जिम्मेदारी तथा नियंत्रण के सम्यक व्यवहार के लिए तैयार हो, लेकिन जब कोई एक समूह या दल राज्य को कैद करने को संगठित होते हैं या इसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो किसी समाज के लिए इनका सामना करना बिना किसी अहिंसक प्रतिरोध के सम्भव नहीं हो सकता है। हम लोकतंत्र की परिधियों में रहकर ही संविधान के मूल उद्देश्यों को बचा सकते हैं।

यह कम चिंताजनक नहीं कि सत्ता का केन्द्रीयकरण होने के बराबर संकेत मिल रहे हैं। केन्द्र में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां दिख रही है। आखिर क्यों देश में फिर आपातकाल की आशंकाएं घर करती जा रही है? गत वर्षो में भारत के राजनीतिक तंत्र का सम्प्रदायीकरण करने और पुरातनवाद को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने लगे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को

ही नेपथ्य में डाला जा रहा है। नागरिक का अधिकार और सम्मान बड़ा प्रश्न है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि लोकतंत्र का पौधा, चाहे जिस प्रकार का हो, अधिनायकवाद के वातावरण में विकास और उन्नति प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह है।

अगर हम लोकनायक जय प्रकाश जी के कथन को याद करें तो हमारे लोकतंत्र के टूटने का आसन्न खतरा नहीं है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें वे सब दोष हैं जिनके कारण लोकतंत्र दूसरे देशों में समाप्त हो गया। लोकतांत्रिक मूल्यों की चेतना के बगैर लोकतंत्र निर्जीव और ढांचा भर रह जाएगा। इस बुनियादी कमजोरी की परख हमें 1975 की आपात् स्थिति में हो चुकी है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के जनप्रतिरोध के लिए 'सम्पूर्णक्रान्ति' का नारा दिया था। कांग्रेस ने लोकतंत्र से खिलवाड़ किया तो भाजपा ने भी सम्पूर्णक्रान्ति के लक्ष्य को कमजोर किया है। इन दिनों भाजपा वर्चुअल रैली के नाम पर जनता को धोखा देने और झूठे प्रचार को बढ़ावा दे रही हैं। यह राजनीति की नैतिकता और निष्पक्षता को नष्ट करने की साज़िश है तथा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है।

कांग्रेस और भाजपा दोनों ने केन्द्र और राज्यों में सरकारें चलाई हैं। दोनों की आर्थिक नीतियां एक समान होने के फलस्वरूप देश में पूंजीवादी ताकतों को बढ़ावा मिला है। गैरबराबरी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है। दोनों ने संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सामान्य आदमी को ताकतवर बनाने के बजाय उसको असहाय, बाजार के अधीन करने का काम किया है। इनके कारण संवैधानिक संस्थाओं में जनविश्वास को खतरा उत्पन्न हुआ है।

आजादी के 74वें वर्ष में सामाजिक–आर्थिक विषमता, राजनीतिक विभेदकारी नीति–रीति, में कोई सुधार नहीं हुआ। बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का स्पष्ट मत था कि भारत के स्वतंत्र होने से ही

सब कुछ साध्य होगा, ऐसी बात नहीं। भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार समान हों और हर एक के व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर मिल सके।

यह बात तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी मानते थे कि आज का भारत उनकी पीढ़ी के सपनों का भारत नहीं है। राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र में आई गिरावट से वे चिंतित रहते थे। उनका कहना था कि प्रशासन की स्पष्ट नीति हो, दृढ़ता से कार्यान्वयन हो लेकिन कार्यान्वयन करने वालों का चरित्र संदेह रहित होना चाहिए। आचरण में ईमानदारी और चरित्र की शुद्धता पर उनका विशेष बल था।

विकास का नियोजन समाजवादी नहीं होने से देश के विविध तबके किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, युवा, कारीगर, महिलाएं, वंचित और शोषित ही बने रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ने से नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। छात्र–छात्राओं की आवाज को कुचला जा रहा है। वैश्वीकरण, पूंजीवाद, उदारीकरण, निजीकरण के जरिए पूंजीवादी ताकतों को ही लूट की छूट मिली हुई है।

देश के समक्ष आज जो गम्भीर समस्याएं हैं इनका हल पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं समाजवादी व्यवस्था से होगा। कर्ज के बोझ से लदा हजारों किसान फांसी के फंदे पर झूल चुका है। अधिकाधिक मुनाफा और सहूलियतों के साथ पूंजी घरानों को आमंत्रित करना देश की संप्रभुता, स्वावलम्बन, आजीविका पर हमला है। आत्मनिर्भरता का यह तथाकथित तरीका बहुत घातक होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपना एजेण्डा देश का राजनीतिक एजेण्डा बनाना चाहता है। वह समाज को जातिवाद और सम्प्रदायवाद को सर्वोच्च स्थान दिलाने में जी–जान से जुटा है। आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा न लेने वाले और आपात काल लगाने वाले दोनों एक ही नाव के सवार हैं।

जाति और जातीयता का सर्वाधिक विरोध डॉ0 भीमराव अम्बेडकर और डॉ0 राममनोहर लोहिया ने

किया। डॉ0 अम्बेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था मनुष्य को संवेदनहीन बनाती है। जाति ने जन चेतना को मार दिया है। उसने जनजागरण को असम्भव बना दिया है। जातिप्रथा में योग्यता और गुण के लिए कोई स्थान नहीं। यह जातिप्रथा न केवल मानव गरिमा के विरूद्ध है बल्कि समतामूलक समाज के स्वप्न के विरूद्ध भी है।

डॉ0 राममनोहर लोहिया तो मानते थे कि हिन्दुस्तान की दुर्गति और हजारों वर्ष की गुलामी के पीछे जातिप्रथा रही है। परिवर्तन के विरूद्ध और स्थिरता के लिए जातिप्रथा एक भयंकर शक्ति है। उन्होंने देश में जाति तोड़ो आंदोलन चलाते वक्त यह नारा भी दिया था–''सोशलिस्टो ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ।'' इस तरह वह समाज में व्याप्त जड़ता को तोड़ना चाहते थे। विशेष अवसर का सिद्धांत इसी को पुष्ट करता है।

अगस्त क्रान्ति के शहीदों का सपना देश में किसान, मजदूर और युवाओं का राज स्थापित करना था ताकि सभी को हक़ व सम्मान का जीवन हासिल हो सके। इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। जिस तरह समाजवादियों ने अगस्त क्रान्ति, जेपी आंदोलन के दौरान अग्रणी भूमिका अदा की थी उसी तरह आज भी उसकी स्वर्णिम परम्परा को आगे बढ़ाते हुए हम समाजवादी भी एकजुट होकर संवैधानिक मूल्यो को बचाने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने की ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास युवा नेतृत्व, युवा साथियों की ताकत, संघर्ष से न डिगने वालों एवं किसानों और गरीब श्रमिकों का जीवंत समूह है।

समाजवादी पार्टी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने को प्रतिबद्ध है। भविष्य में विश्वस्तरीय ढांचागत संरचना तैयार करने की भी योजना है। समाजवाद के जरिए उद्योग, लघु, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग और कृषि के लिए भी आधारभूत संरचना तथा तकनीकी रूप से सक्षम सुविधाओं के

निर्माण हेतु निरन्तर प्रयासशील रहा जाएगा।

समाजवादी पार्टी डिजीटल परिवर्तन की पक्षधर है। यह समय की आवश्यकता है कि भविष्य में इन्टरनेट और डिजीटल टेक्नालॉजी से व्यवस्था प्रभावित होगी। समाजवादी पार्टी इस वास्तविकता को पहले से ही महसूस कर चुकी थी। इस परिवर्तन की बुनियाद समाजवादी सरकार में रखी गई थी जब छात्र एवं छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किये गये। समाजवादी सरकार में छात्र–छात्राओं को 18 लाख लैपटाप बांटे गए थे ताकि वे आज की दुनिया से जुड़ सकें। सोशल मीडिया के कारण सुविधायें विकसित हुई है। इस माध्यम में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता जरूरी है इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रणाली को ताकत मिली है। बैंकिंग सहित हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है।

दुनिया तकनीकी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है, नित नए आविष्कार हो रहें हैं। प्रगति के लिए समय के साथ चलना जरूरी है। व्यवस्था में बदलाव की सुविधा के लिए समाजवादी सरकार में आधुनिकतम तकनीक के साथ यूपी डायल 100 नम्बर सेवा शुरू की गई थी जिससे किसी घटनास्थल पर बिना देर किए पुलिस पहुंच सके। महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन सेवा, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 समाजवादी एम्बूलेंस सेवा तथा गर्भवती महिलाओं के लिए 102 नम्बर एम्बूलेंस सेवा की व्यवस्था की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष 55 लाख महिलाओं को दिये जाने की व्यवस्था समाजवादी सरकार में लागू थी।

समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ितों और अन्याय के शिकार लोगों के साथ खड़ी रही है। इसलिए कोरोना संकट में दर–बदर हुए श्रमिकों को राहत पहुंचाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिनरात लगे रहे। हजारों श्रमिकों एवं जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कराई गई। जो श्रमिक इस दौर में जान गंवा

बैठे उनके परिवारीजनों को एक–एक लाख रूपए की मदद दी गई। रास्ते में फंसे श्रमिक परिवारों को उनके घर भिजवाया गया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद मोहम्मद आज़म खाँ के साथ जो व्यवहार भाजपा सरकार कर रही वह अनैतिक एवं अमानवीय है। लोकतंत्र में सरकार का आचरण बिना रागद्वेष का होना चाहिए।

भाजपा सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपमानित करने और यातना देने के लिए झूठे केसों में फंसाया जाता रहा है। भाजपा समझती है कि इससे समाजवादी पार्टी का मनोबल तोड़ा जा सकता है। भाजपा इसमें कभी सफल नहीं हो सकेगी। भाजपा ने अब तक कोई वादा नहीं निभाने का विश्वरिकार्ड बनाया है। समाज का हर वर्ग उसकी कुनीतियों से बुरी तरह त्रस्त है।

गांधी जी का सभी धर्मो के प्रति समभाव का आग्रह, अधर्म का विरोध और सत्याग्रह तथा अहिंसा का दर्शन, डॉ0 राममनोहर लोहिया का अन्याय के खिलाफ सिविल नाफरमानी का संघर्षशील मार्ग और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लोकनीति एक नए परिवर्तन की बुनियाद बन सकती है। अगर मानवता को पूंजी और सत्ता की हिंसा से मुक्ति दिलानी है तो समाजवाद का सपना देखना होगा। समाजवाद महज एक राजनैतिक विचारधारा ही नहीं बल्कि एक सम्पूर्ण जीवनदर्शन भी है। भारत में समाजवादी होने का अर्थ है, समाजवादी दर्शन के अनुसार अपने नित्य व्यवहार को ढालना। इसका अर्थ है सादगी, मितव्ययिता, परस्पर व्यवहार में समता, प्रेम, ईमानदारी, नेतृत्व के प्रति निष्ठा तथा साध्य–साधन की पवित्रता को अपनाना।

8 अगस्त 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक युद्ध का आव्हान करते हुए गांधीजी ने हर हिन्दुस्तानी से कहा था ''वह अपने को आजाद समझे। लड़ाई छिड़ने पर स्वभावतः

उनके मार्गदर्शन के लिए कोई नेता बाहर नहीं रहेंगे, इसलिए उनको ही अपना नेता बनकर अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपना कार्यक्रम बनाकर युद्ध को चलाना होगा।''

आज यही उद्‌बोधन समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी के लिए मार्गदर्शन का प्रेरक संदेश है। सन् 2022 में परिवर्तन के लिए खुद से ही हर समाजवादी कार्यकर्ता को पहल करनी होगी। 2022 में समाजवादी सरकार का काम जनता के नाम का उद्‌घोष रहेगा।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए युवाओं, किसानों, मेहनतकशों और समाज के विचारशील वर्गों की सहभागिता ही हमारी ताकत होगी। देश की विविधता को नष्ट करने की साजिशों के दौर में संवैधानिक मूल्यों को बचाने तथा हर नागरिक का समृद्ध एवं सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। सन् 2022 के लिए अपनी तैयारियों में हमें कोई कसर नहीं रखनी है। लोकतंत्र को बचाने के सघन अभियान में आप सभी साथियों से एकजुटता और निष्ठा के साथ अनवरत सक्रियता की अपेक्षा करता हूँ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी एवं
पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

9 अगस्त 2020